THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMARAM): (a) and (b) the need to defer implementation of the ban on the import of products using certain dyes and chemicals has already been taken up with the German Government through diplomatic channels. As indications are that such deferment is being considered, government do not, for the present, propose to send a delegation to Germany in this regard.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बिना किसी उपयोग के पड़ी राशि ।

***649 श्री कनकसिंह मोहन सिंह मंगरोला :**
श्री ईश दत्त यादव :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पास जमा कराई गई भारी धनराशि गत अनेक वर्षों से बैंकों में बिना किसी उपयोग के पड़ी है,

(ख) यदि हां, तो इस धनराशि का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस धनराशि के उपयोग हेतु किए जाने वाले ठोस उपायों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री ० ए ०संगमा

(क) से (ग) क०रा०बी० योजना मुख्यत: क०रा०बी० अधिनियम के अंतर्गत आने वाले नियोजकों और कर्मचारियों द्वारा अंशदान के वित्तपोषित की जाती है। नियोजक मजदूरी के 4 प्रतिशत की दर से और कर्मचारी 1.5 प्रतिशत की दर से अंशदान देते हैं। अधिनियम के अंतर्गत एकत्र किये गये अंशदान, लेकिन जिनका योजना के अंतर्गत हुए व्यय को तत्काल चुकता कहने की आवश्यकता नहीं होती है, उनका निर्देश नियमों के अधीन निश्चित पटर्न के अनुसार बैंकों के सावधि जमा और केन्द्रीय सरकार के विशेष जमा खाता में कर दिया जाता है । एक बीमा योजना होने के कारण बीमित व्यक्तियों की चिकित्सा सुविधा लागत और रुग्णता, प्रसूति, अपगता और मृत्यु के कारण आने वाली अप्रत्याशित आकस्मिकताओं के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान को पूरा करने के लिए ई०एस०आई० निगम द्वारा पर्याप्त आरक्षित निधियां रखना आवश्यक होती हैं । प्रशासनिक व्ययों के अलावा, वर्ष 1993–94 के दौरान, 496.93 करोड़ रुपये के अंशदान आय की तुलना में बीमित व्यक्तियों को विविध लाभ प्रदान करने के लिए ई०एस०आई० निगम द्वारा 487.53 करोड़ रुपये व्यय किए गए । तथापि, ई०एस०आई० चिकित्सा में और सुधार लाने के लिए, निगम ने 1–4–94 से प्रति बीमित व्यक्ति चिकित्सा सुविधा पर होने वाले व्यय की उच्चतम सीमा 345 रुपए से बढ़ाकर 410 रुपए प्रतिवर्ष कर दी है । बीमित व्यक्तियों को व्यावसायिक बीमारियों के तुरंत निदान/पहचान के लिए, निगम ने राज्य सरकारों से बिना कोई अंशदान लिए अपनी निजी लागत पर 4 व्यावसायिक बीमारी केन्द्रों की स्थापना का निर्णय लिया है ।

Unemployment caused by liberalisation

*650. SHRI K. R. MALKANI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have seen the report of 'Indian Express' dated 2nd May, 1995 on Trade Unions distress over large scale unemployment caused by liberalisation;

(b) what is Governments reaction in the matter; and

(c) what are the Employment Exchange figures in the subject?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The issues raised in the news item published in the "Indian Express" on May, 2, 1995 are of general